



SAFALTA CLASSTM

An Initiative by **अमरउजाला**

INDIAN POLITY BY- SUJEET BAJPAI SIR



Question No: 1

संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस/किन नाम/नामों से किया गया है?

- (a) भारत तथा इंडिया (b) केवल भारत
(c) हिंदुस्तान तथा इंडिया (d) भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया

By which name/names is our country mentioned in the Constitution?

- (a) Bharat and India (b) Bharat only
(c) Hindustan and India (d) Bharat, Hindustan and India

Question No: 2

निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं?

~~I. समाजवाद~~

II. ग्राम स्वराज

~~III. पंथनिरपेक्षता~~

IV. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न

Which of the following words of the following words have been added to the Preamble by the 42- Amendment?

~~I. Socialist~~

~~II. Gram Swarajya~~

~~III. Secular~~

~~IV. [Sovereign]~~

Integrity
#

Question No: 2

सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूटों के उपयोग से कीजिए :

Select the correct answer by using the code given below:

कूट / Code

(a) I, II, III

(b) I and III

(c) I, II, IV

(d) II, III, IV

Question No: 3

5

In the context of the Preamble of Indian Constitution which of the following sequence is correct?

(a) ~~Republic~~, People's Democratic, Secular, Socialist, Universal, Sovereign

(b) Sovereign, Socialist, Democratic, People's, Secular, Republic

(c) Sovereign, Socialist, People's, Democratic, Secular, Socialist Republic

(d) ~~Sovereign~~, Socialist, Secular, (Democratic, Republic)

Question No: 3

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है?

- (a) गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न
- (b) सार्वभौम सत्तासंपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र
- (c) सार्वभौम सत्तासंपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र
- (d) सार्वभौम सत्तासंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र

Question No: 4

संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है?

1. पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत "ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव" अंततोगत्वा उद्देशिका बना।
2. इसकी प्रकृति न्याययोग्य (Justiciable) नहीं है।
3. इसका संशोधन नहीं किया जा सकता।
4. संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द (Override) नहीं कर सकता।

कूट :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (c) केवल 1, 2 और 3 |
| (b) केवल 1, 2 और 4 | (d) केवल 2, 3 और 4 |

Question No: 4

Consider the following statements in regards to the Preamble of Constitution and select the correct one using the code given below –

1. ~~✓~~ The objectives Resolution by Jawaharlal Nehru finally became Preamble
2. ~~✓~~ It is non-Justiciable.
3. ~~✗~~ It can't be amended
4. ~~✓~~ Preamble cannot override the specific provision of the Constitution

Code:

(a) only 1 and 2

~~✗~~ (c) only 1,2 and 3

~~✓~~ (b) only 1,2 and 4

~~✗~~ (d) only 2,3 and 4

Question No: 5

निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को "हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली" कहा?

- (a) जवाहरलाल नेहरू
- (b) वल्लभभाई पटेल
- (c) बी.आर. अंबेडकर
- (d) के.एम. मुंशी

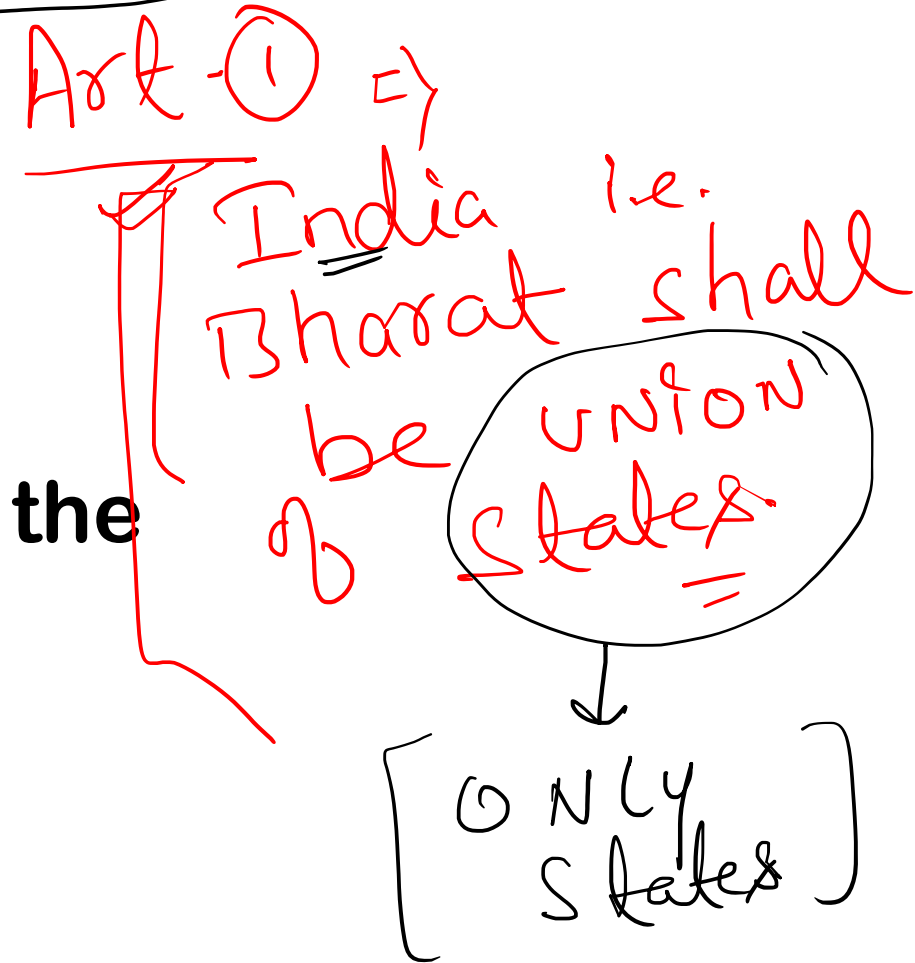
Question No: 5

Who among the following called the Preamble of Indian Constitution “the horoscope of our sovereign, democratic republic”?

- (a) Jawaharlal Nehru
- (b) Vallabhbhai Patel
- (c) B.R. Ambedkar
- (d) K.M. Munshi
- (e) ~~Mahatma Gandhi~~

According to Article 1, the territory of India can be classified into three categories:

1. Territories of the states
2. Union territories
3. Territories that may be acquired by the Government of India at any time.



अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. राज्यों के प्रदेशों
2. केंद्र शासित प्रदेश
3. ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं।

Area of Territory of India (7) Area of Union of India.

→
Article 2 grants two powers to the Parliament:

(a) the power to admit into the Union of India new states; and

(b) the power to establish new states.

अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है:

(क) भारत के नए राज्यों के संघ में प्रवेश करने की शक्ति;
और

(ख) नए राज्यों की स्थापना की शक्ति ।

The first refers to the admission of states which are already in existence while the second refers to the establishment of **states which were not in existence before.**

पहला उन राज्यों के प्रवेश को संदर्भित करता है जो पहले से अस्तित्व में हैं जबकि दूसरा उन राज्यों की स्थापना को संदर्भित करता है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे ।

Article 3, on the other hand, relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India.

In other words, Article 3 deals with the internal re-adjustment of the territories of the constituent states of the Union of India.

दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारत संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या बदलाव से संबंधित है।

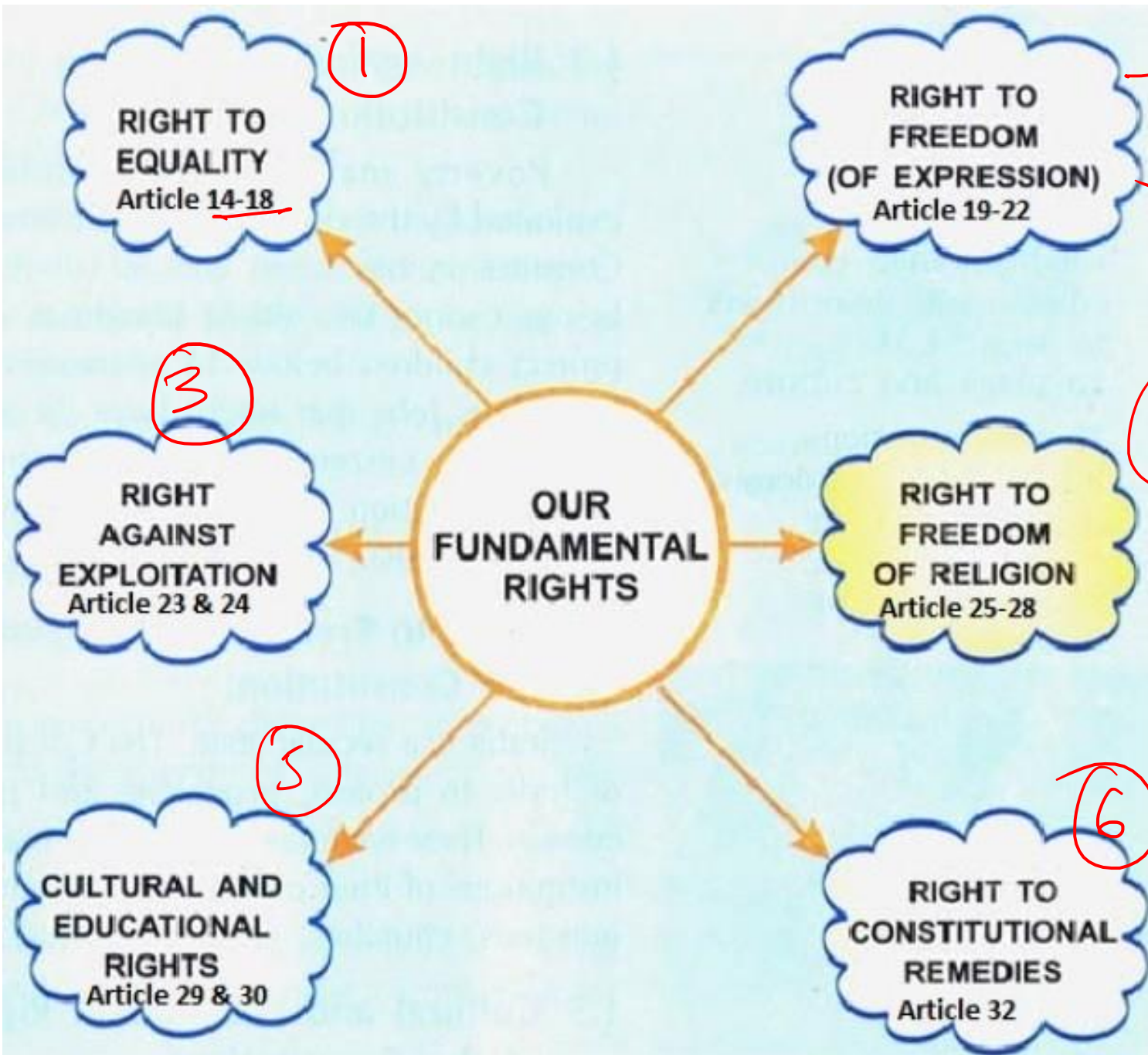
दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 3 भारत संघ के घटक राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुन समायोजन से संबंधित है ।

Part-3 (Art-12-35)

Fundamental Rights



from
USA
Art =
(14-32)



The Fundamental Rights are enshrined in Part III of the Constitution from Articles 12 to 35.

In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA (i.e., Bill of Rights).

मौलिक अधिकार संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रतिष्ठापित हैं ।

इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (यानी अधिकारों के विधेयक) से प्रेरणा प्राप्त की।

Originally, the Constitution provided for seven Fundamental Rights-

- 1. Right to equality (Articles 14–18)**
- 2. Right to freedom (Articles 19–22)**
- 3. Right against exploitation (Articles 23–24)**

मूल रूप से संविधान में सात मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था-

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

4. Right to freedom of religion (Articles 25–28)
5. Cultural and educational rights (Articles 29–30)
6. Right to property (Article 31) ⇒ (deleted ⇒ 44th/1978)
7. Right to constitutional remedies (Article 32)

↳ Present legal Rk ⇒ Art 300A
(Part-12)

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
7. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

✓
However, the right to property was deleted from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978.

It is made a legal right under Article 300-A in Part XII of the Constitution. So at present, there are only six Fundamental Rights.

हालांकि, 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।

इसे संविधान के भाग 12वीं में अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसलिए वर्तमान में केवल छह मौलिक अधिकार हैं ।

Features of Fundamental Rights:

1. Some of them are available only to the citizens.
2. They are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them.

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं:

1. उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
2. वे निरपेक्ष नहीं बल्कि निर्बंधन के अधीन हैं। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

3. They are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement, if and when they are violated.

Art - 32

4. They are defended and guaranteed by the Supreme Court.

3. वे Justiciable हैं, व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में स्थानांतरित करने की अनुमति है, अगर और जब वे उल्लंघन कर रहे हैं।

4. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका बचाव और गारंटी दी जाती है।

~~RR~~ FAO
5. They can be suspended during the operation of a National Emergency except the rights guaranteed by Articles 20 and 21.

RT to Internet Access

5. वे अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटी अधिकारों को छोड़कर एक राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है।

✓ 6. Their application to the members of armed forces, para-military forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the Parliament (Article 33).

6. सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप सेवाओं के सदस्यों को उनके आवेदन को संसद (अनुच्छेद 33) द्वारा प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है।

7. Fundamental rights can be restricted while martial law is in force in any area.

Martial law means 'military rule' imposed under abnormal circumstances to restore order (Article 34).

7. मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है जब मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू है।

मार्शल लॉ का मतलब है 'सैन्य शासन' (अनुच्छेद 34)।